

सम्पादकीय

स्थानीय स्तर पर लोग टीबी
के खिलाफ भारत की लड़ाई
में दे रहे अपना योगदान

वर्ष 2025 तक भारत को 'टीबी मुक्त' बनाने के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) पूरी गति से चल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत टीबी को भारत से पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए हर टीबी मरीज की पहचान करके, उसे अधिसूचित करने की पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ने तैयार की है। यह व्यवस्था भी की गई है कि टीबी मरीजों को समय पर दवा मिले। दरअसल इग रेसिस्टेंट टीबी मरीजों के इलाज में महंगी दवाओं का इस्तेमाल होता है। ऐसे में नरेन्द्र मोदी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इन्हें ये महंगी दवाएं भी उपलब्ध हों। टीबी मरीजों का इलाज तब ही प्रभावी होता है, जब उनकी पोषण जरूरतें पूरी हों। टीबी मरीजों का सही पोषण सुनिश्चित करने के लिए सरकार मरीजों की आर्थिक मदद भी कर रही है। टीबी मामलों की अधिसूचना एनटीईपी के सही दिशा में काम करने का एक प्रमुख संकेतक है। वर्ष 2019 में रिकार्ड 24 लाख से अधिक मामलों की पहचान की गई। यह एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है, क्योंकि इससे अनुमानित मामलों और रिपोर्ट किए गए मामलों के बीच का अंतर समाप्त हो गया। जब यह अंतर समाप्त होता है तो अधिक से अधिक टीबी मरीजों का इलाज हो पाता है और इन मरीजों से आगे संक्रमण फैलने पर अंकुश लगता है। कोविड महामारी का असर बहुत व्यापक रहा है। इसका असर टीबी कार्यक्रम पर भी पड़ा। वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में टीबी मामलों की अधिसूचना 25 प्रतिशत घट गई। लेकिन 2021 में यह स्थिति सुधारी और 21 लाख टीबी मामले अधिसूचित किए गए। यह 2020 की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। यह दिखाता है कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 'टीबी मुक्त भारत' बनाने के लिए पूरी संजीदी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'सबका साथ, सबका प्रयास' की बात कहते हैं। इसी भावना की वजह से आज जमीनी स्तर पर 'टीबी मुक्त भारत' बनाने का कार्यक्रम जन आंदोलन बन गया है। सरकार के साथ-साथ विभिन्न स्तर के जन-प्रतिनिधियों, समाज और सामाजिक संगठनों की ताकत जुड़ गई है। सभी के साझा प्रयास से सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। जन-प्रतिनिधियों और समाज के प्रभावशाली प्रतिनिधियों के प्रयासों ने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे कि निक्षय पोषण योजना में टीबी रोगियों का लाभान्वित करने में सहयोग किया। इससे कठिन समय में अधिसूचित रोगियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की। अप्रैल 2018 से दिसंबर 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार ने निक्षय पोषण योजना के तहत 57 लाख टीबी मरीजों को कुल 1,487 करोड़ रुपये से अधिक की सीधी आर्थिक मदद की है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बच्चों को टीबी से मुक्त दिलाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत घर-घर जाकर टीबी से ग्रसित बच्चों के बीच टीबी निवारक सेवाओं का दायरा बढ़ाया गया है। वर्ष 2019 में अधिसूचित टीबी रोगियों में से तकरीबन 47 प्रतिशत परिवारों वें यहां स्वास्थ्यकर्म गए। इनमें से पांच लाख से अधिक टीबी से ग्रसित बच्चों की पहचान की गई। इन बच्चों में से 78 प्रतिशत को टीबी प्रीरैटिव थेरेपी (टीपीटी) का लाभ मिला। इसी तरह से पीएलएचआर्डी (एचआर्डी वाले टीबी रोगी) को भी इस कार्यक्रम के तहत जरूरी मदद दी जा रही है। टीबी उन्मूलन के लिए भारत नई तकनीक विकसित करने और इन्हें अपनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। भारत ने एक अत्यधिक प्रभावी 'मेक इन इंडियाएट' उत्पाद वें रूप में टरुनेट डायगोनेस्टिक टेस्ट विकसित किया है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित है और आज यह पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध है। इसी तरह से टीबी के संभावित मरीजों की पहचान के लिए कृतिम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल समेत अन्य आधुनिक तकनीकी समाधानों की संभावनाओं को टोटला जा रहा है। टीबी के कुल मरीजों में से करीब 70 प्रतिशत ऐसे हैं, जो निजी क्षेत्र में इलाज कराना चाहते हैं। इनका सही इलाज हो लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत यह रणनीति अपनाई गई है कि जहां कोई रोगी हो, वही हमें पहुंचना है। इससे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रभाव बढ़ा है। वर्ष 2019 में पहली बार ऐसा हुआ कि निजी क्षेत्र के अस्पतालों से तकरीबन सात लाख टीबी मरीजों को अधिसूचित किया गया।

नए वैश्विक ढांचे में भारत की हैसियत उसकी अंतरराष्ट्रीय साख बढ़ाने एवं राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो रही

पिछले कुछ अर्स से दुनिया बड़े उत्थल-पृथुल भरे दौर से गुजर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने इस हल्याल को और बढ़ा दिया है। इससे कई पुरानी साझेदारियां दांव पर लग गई हैं तो तमाम नए रिश्ते उभरते नजर आ रहे हैं। वैश्विक ढांचे की जटिलता इतनी बढ़ गई है कि दो मित्र देश एक पड़ाव पर साथ दिखते हैं तो अगले पड़ाव पर उनके हितों में टकराव होने लगता है। ऐसे में सभी देशों को अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव करना पड़ रहा है। भारत के लिए बदलाव की यह चुनौती इस कारण और विकराल हो गई कि रूस के साथ जहां हमारे ऐतिहासिक प्रगाढ़ रिश्ते हैं, वहीं विगत कुछ दशकों के दौरान अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ हमारे संबंध नई ऊँचाई पर पहुंचे हैं। युरोप में करीब महीने भर से जारी जंग ने इन दोनों ही गुटों में दरार और तकरार कहीं ज्यादा बढ़ा दी है। इसके चलते दुनिया के तमाम देशों को किसी न किसी पाले में खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसे धर्मसंकर की स्थिति में भारत किसी पाले में खुलकर खड़े हुए बौर अपने हितों को पोषित करने में सफल रहा। भारतीय हितों के संरक्षण में संतुलन साधने की हमारी विदेश नीति के पाकिस्तान जैसे पेसोसी देशों का कायल होना उसकी कामयाबी को ही बयान करता है। बीते दिनों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सार्वजनिक सभा में भारतीय विदेश नीति की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। पाकिस्तान जैसे देश से ऐसी तारीफ दुर्लभ ही मिलती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय विदेश नीति की इस सफलता में भारत के बढ़ते कद की अहम भूमिका रही। भारत गिनती के उन दौशों में रहा, जिसके प्रधानमंत्री की रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार बात हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही देशों से संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की बात कही। इतना ही नहीं जहां भारत रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसे अलग-थलग करने के प्रयासों का समर्थन नहीं कर रहा, वहीं उसे रूस को यह हिदायत देने में भी गुरेज नहीं कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। मंगलवार को ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जानसन से वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रसों को संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र का पालन करना चाहिए। भारत के इसी संतुलित रुख का नतीजा है कि रूस के खिलाफ स्पष्ट रुख न अपनाने को लेकर हो रही आलोचनाओं के बावजूद उसे पश्चिमी देशों के कोप का भाजन नहीं बनना पड़ा।

अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, पढ़ें एक्सपर्ट व्यू

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हाल ही में ब्याज दरों में एक चौथाई प्रतिशत की वृद्धि की है। साथ ही अभी इसमें और बढ़ोतारी के स्पष्ट संकेत दिए हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने 2018 के बाद पहली बार ब्याज दर बढ़ाई है। पिछले चार दशकों में सबसे तेज मुद्रास्फीति से निपटने के लिए फेड ने अभियान शुरू किया है। वहीं अनुमान है कि वर्ष 2023 में फेड की दरें 2.8 प्रतिशत तक पहुंच सकती हैं। इस तरह अमेरिकी फेड ने अब कठोर मौद्रिक नीति का रास्ता अपना लिया है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी मौद्रिक नीति पर अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ानी चाही दी जाएगी।

उपलब्धता बनो रहे। अब भारतीय ब्यवस्था पटरी पर लौट आए और लोगों को गत्स्तर में सस्ती की जरूरत है, लेकिन यूपी के ब्याज दरों में वृद्धि के बारे आरबीआइ पर भी ब्याज वृद्धि का दबाव होगा। आरबीआइ ब्याज दरों में वृद्धि करेगा, तो निवेशक भारत से निकाल सकते हैं। ऐसे में नीति पर आरबीआइ को सावधानी से निर्णय लेना इस समय ब्याज दरों में निवेशकों को रोकने में मदद सकती है, लेकिन महंगे तरीफ अर्थव्यवस्था की रिकवरी दूरी

निण्यों का असर आरबीआइ के ब्याज दरों पर अवश्य पड़ेगा। अमेरिका में जैसे-जैसे ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी, वैसे-वैसे अमेरिका और भारत सरकार के बांड के बीच का अंतर कम हो जाएगा, जिससे वैश्विक निवेशक भारतीय प्रतिभूतियों से पैसा निकालेंगे। इसलिए भारतीय बांड बाजार से एफपीआइ के निकासी को रोकने के लिए आरबीआइ को ब्याज दरें बढ़ाने होंगी। अभी प्रथम स्तर पर यूएस फेड ने केवल 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की है, इसलिए अभी आरबीआइ यूएस फेड के निण्य से बिना प्रभावित हुए मौद्रिक नीति

मारबीआइ के घोषित दायरे में रही है। लेकिन जनवरी और फरवरी में खुदरा महंगाई दर आरबीआइ के घोषित दर से ज्यादा रही। फरवरी में खुदरा महंगाई दर आठ माह के अच्यतम स्तर पर पहुंच गई है। मारबीआइ का पहले अनुमान था कि मार्च 2023 तक खुदरा महंगाई दर 4.5 प्रतिशत रहेगी, लेकिन अब इस अनुमान में भी बदलाव की पूरी भावना है। थोक महंगाई दर भी अगातर कई माह से दो अंकों में नी हुई है। इस तरह आरबीआइ ने भी भविष्य में ब्याज दरों में वृद्धि के लिए बाध्य होना ही होगा। डालर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होने

अमेरिकी ड्रेजरी उपकरणों में पैसा निकाला जाता है। इसका असर भी रुपये पर पड़ेगा। महंगे हो सकते हैं लोन : यूएस फेड के निर्णय के कारण ब्याज दरों में वृद्धि होने पर भारतीय लोन महंगे हो सकते हैं। पर्सनल लोन और अधिकांश डेट प्रोडक्ट की ब्याज दर फिक्सड होती है, लेकिन अधिकांश होम लोन फ्लॉटिंग रेट पर आधारित होते हैं। आरबीआई पर यूएस फेड का दबाव लगातार बना हुआ है, जिससे कैलेंडर वर्ष 2022 के प्रथम छमाही में भारत में भी ब्याज दरों में बढ़तेरी देखने को मिल सकती है, जिससे आपके होम लोन की दरों में बढ़तेरी होगी। कर्ज लेने वालों को अब सतत बढ़े गले ब्याज दर के विभिन्न चक्रों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप नया होम लोन लेने जा रहे हैं, तो वर्तमान रिकार्ड निम्न दरों पर बहुत ज्यादा कर्ज नहीं लें, अन्यथा भविष्य में आपका बजट बिगड़ सकता है। फेड के ब्याज दरों में वृद्धि के बाद डालर की स्थित लगातार मजबूत बनी हुई है, जिससे रुपये पर लगातार दबाव बना हुआ है। आरबीआई के पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार 11 मार्च को खत्म हुए हफ्ते के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 10 अरब डालर घट गया है। बीते दो साल में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। सात मार्च को डालर के मुकाबले रुपया 77 के स्तर को पार कर गया था। रुपये में और गिरावट को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप किया और बाजार में डालर की बिक्री की। अनुमान के अनुसार रिजर्व बैंक ने एक सप्ताह के दौरान करीब एक डालर प्रतिदिन के हिसाब से डालर बाजार में उतारा। इसके बावजूद देश का विदेशी मुद्रा भंडार 631.92 अरब डालर के आसपास बना हुआ है। फेड निर्णय के बाद वर्तमान में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार के कारण रुपये की स्थिति कुछ बेहतर बनी हुई है, लेकिन अभी भी विदेशी निवेश को रोकना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। भारत के लिए मिले-जुले असर की आशंका : अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में वृद्धि से एक तरफ लोन महंगा होगा, लेकिन दूसरी तरफ ब्याज में वृद्धि से बचत धारकों को अधिक लाभ होगा। अब तक ब्याज दरों में लगातार कटौती के कारण केंद्र सरकार को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकरन्या समृद्धि योजना इत्यादि महत्वाकांक्षी योजनाओं में ब्याज दर में कटौती करना पड़ रही थी। परंतु अब फिर से अधिकांश बचत योजनाओं में अच्छे ब्याज दर की प्राप्ति हो सकेगी। इस तरह बचत धारकों के लिए यह घटनाक्रम खुशखबरी लेकर आया है। फेड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि से भारत में महंगाई और बढ़ सकती है। फेड के इस फैसले से डालर और मजबूत होगा और रुपया कमज़ोर पड़ जाएगा। रुपये के कमज़ोर होने पर भारत सरकार को कच्चे तेल के लिए और अधिक कीमत चुकानी होगी, परिणामस्वरूप पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हो रही है। पेट्रोल-डीजल महंगा होने से परिवहन की दरें बढ़ जाएंगी, जिससे अधिकांश वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होंगी। इसके अलावा, आयात होने वाले सभी प्रकार के कच्चे माल की खरीदारी के लिए पहले से अधिक रुपये खर्च करने होंगे, जिस कारण उन कच्चे माल से बनने वाले उत्पाद महंगे हो जाएंगे। सोने की कीमत में गिरावट : डालर की मजबूती सोने को कमज़ोर करे गी, जिसका असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिलेगा। इस निर्णय के बाद सोने में लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सोना 54 हजार से टूटकर 51 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पर्हुच चुका है। निकट भविष्य में यह आसानी से 46 हजार रुपये के स्तर को एक बार फिर से छु सकता है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच एक अच्छी बात यह हो सकती है कि इससे निर्यात नौ प्रोत्साहन मिल सकता है। यह सही है कि कमज़ोर रुपया आयात को महंगा करता है, परंतु निर्यात को सस्ता बनाता है। भारतीय वस्तुएं कमज़ोर रुपये वें कारण वैश्वक बाजार में सस्ती हो जाती है। वैश्वक बाजार में कठोर प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है। ऐसे में निर्यात की वस्तुएं सस्ती होने पर उसकी मांग में स्वतः वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार निर्यात बढ़ जाता है। उल्लंघनीय है कि फरवरी में भारतीय निर्यात दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जैसे-जैसे यूएस फेड के अगले चक्रों की वृद्धि होगी, वैसे-वैसे निर्यात में भी वृद्धि होगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुखद स्थिति होगी।

जाति आधारित आकांक्षाओं ने जातीय अस्मिता की राजनीति करने वालों को दिया झटका

राजनीति समाज को बदलती है तो समाज भी राजनीति को बदलता है। इसीलिए समाज एवं राजनीति के रूप में परिवर्तन होता रहता है। परन्तु अवधारणाएं टृटी हैं जाति एवं अनेक सामाजिक असमिताओं को थोड़ी देर के लिए ही सही, पीछे थकेल दिया है। हालांकि जाति अभी भी जनतांत्रिक गोलबंदी की राजनीति के प्रभावी

जाति एवं अनेक सामाजिक अस्मिताओं को थोड़ी देर के लिए ही सही, पैछे धक्कल दिया है। हालांकि जाति अभी भी जनतांत्रिक गोलबंदी की राजनीति के प्रभावी जातियों से परे विकास की चाह से संचालित होने वालों का एक बड़ा समूह तैयार किया है। दूसरा, जातीय अस्मिता की राजनीति करने वालों को एक बड़ा झटका दिया है।

भारतीय शासन, प्रशासन एवं
जननीति को भी प्रभावित किया है।
से तो हर दल एक लाभार्थी समूह
विकसित करता है, किंतु भाजपा
ने इबल इंजन सरकारों ने केंद्र

राजनीतिक कार्यक्रमों से इन समूहों को एक ऐसे समुदाय में तब्दील कर दिया है, जिनमें आकांक्षी चेतना विकासमान रहती है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें विकास योद्धा का नाम दिया। भाजपा ने एक ऐसी राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी है, जिसके कारण दलित, गरीब एवं उपेक्षित तबकों का एक बड़ा गोट बसपा जैसे दलित सशक्तीकरण की राजनीति करने वाले दल से छिटक कर उसकी तरफ जा रहा है। इसे मैं एक नई अस्मिता के उभार के रूप में देखता रहा हूं। यह अस्थायी होती है और बनती-बिंगड़ती भी रहती है, पर यह प्रभावी होती है। इसे स्थायी बनाए रखना राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मद्र प्रधान ने चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही गरीब कल्याण को एक बड़े वृत्तांत के रूप में प्रस्तुत किया था। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ किया तो उनका जोर गरीब कल्याण एवं विकास योद्धाओं पर रहा। गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक महत्वपूर्ण विमर्श के रूप में रखा। इस प्रकार दलित एवं हाशिये के समूहों का राजनीतिक पक्ष तय करने में जातीय अस्मितापरक विमर्श से ज्यादा बड़ी भूमिका विकास की चाहत की रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपने सेवाकारी के माध्यम से हाशिये के समूहों के एक भाग में हिंदुत्व की चेतना को प्रखर किया है। इस चेतना ने पिछड़े वर्गों एवं दलित जातियों में जातीय अस्मिता की चेतना के आक्रमक उभार को काफी कुछ संतुलित एवं अनुकूलित करने का काम किया है। संघ एवं उससे प्रभावित अनेक संगठन हाशिये के समाजों में कई दशकों से सेवा कार्य करते आ रहे हैं। संघ परिवर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सूजन के अनेक कार्यक्रम हाशिये के समाजों के बीच संचालित करता है। विद्या भारती संचालित स्कूल दलितों एवं हाशिये के समाजों में शिक्षा प्रसार के माध्यम से पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार बनवासी कल्याण आश्रम शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वावलंबन के कार्यों के जरिये जनजातीय समूहों के बीच हिंदुत्व की चेतना जगा रहा है। हमारे महानगरीय बुद्धिजीवी अपने चश्मे से हाशिये के समूहों को देखने के क्रम में प्रयाः यह तथ्य भूल जाते हैं कि उनकी जरूरतें भिज्ज होती हैं। ऐसे बुद्धिजीवी उनके भीतर अपने जैसे एक 'क्रांतिकारी' की खोज में लगे रहते हैं। वे यह नहीं भांप पाते कि कैसे थीरे-थीरे उनकी जीवन स्थितियां उनकी मनोदशा में परिवर्तन ला रही हैं। वे यह भी नहीं देख पाते कि पारंपरिक अस्मिताओं के साथ उनके संबंध कैसे बन-बिंगड़ रहे हैं ऐसे में वे उनकी राजनीतिक चाहत में आए परिवर्तन को या तो देख नहीं पाते या फिर देखते भी हैं तो समझ नहीं पाते और समझते भी हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते।

